उत्पादन बढ़ाने की हरसंभव नीतियां आजमाए भारत

यहां स्कैन करें

सौरभ चंद्रा | पूर्व पेट्रोलियम सचिव, भारत सरकार

पिछले तीन दशकों में सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत के आसपास ही क्यों बनी हुई है? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र या सहज शब्दों में कहें, तो उत्पादन क्षेत्र पर्याप्त रोजगार पैदा क्यों नहीं कर पा रहा? इसमें व्यापार घाटा इतना अधिक क्यों है? जाहिर है, हमारे उत्पादन क्षेत्र के वैश्विक मुकाबलों में पिछड़ने के कई कारण हैं। कुछ वजहें तो कमजोर उत्पादन-दक्षता, बुनियादी ढांचे की कमियां, नियामक मंजूरी आदि में लगने वाली लागत आदि हैं। ये उत्पादन माहौल को बेहतर बनाने वाली ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनकी पूर्ति इसलिए जरूरी है, ताकि भारतीय निर्माता घरेलू व विदेशी बाजारों में मुकाबला कर सकें। निस्संदेह, वे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने, रोजगार सृजन और घरेलू व वैश्विक, दोनों बाजार में कड़ी टक्कर देने में सक्षम हैं, पर यह तभी संभव है, जब विनिर्माण की गुणवत्ता बेहतर हो। इसके लिए हमें नवाचार को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा, रक्षा एवं दूरसंचार जैसे खास उद्योगों की मूल्य श्रृंखला का बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही रहे।

मूल्य-वर्द्धन विनिर्माण क्षेत्र की बेहतरी का एक सूचक है। यह कमाई और लागत के बीच का अंतर है। इसमें श्रम लागत, ब्याज, किराया, कर और मुनाफा आदि भी शामिल होता है। यह रोजगार सृजन की एक जरूरी शर्त है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार, खेतिहर मजदूरों के लिए भारत को कम से कम नौ करोड़ नए कृषि रोजगार पैदा करने होंगे। केवल विनिर्माण क्षेत्र इस चुनौती का सामना कर सकता है। सेवा क्षेत्र के बूते यह संभव नहीं। श्रमबल में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सिर्फ 25 फीसदी है, जो जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी से काफी कम है। अत्यधिक कुशल सेवा क्षेत्र विकसित करने से पहले उत्पादन क्षेत्र को एक खास स्तर तक पहुंचना होगा। ये दोनों क्षेत्र एक-दूसरे पर काफी हद तक निर्भर हैं। जैसे, हार्डवेयर के विकास पर सॉफ्टवेयर की उन्नति निर्भर करती है।

जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का अनुभव बताता है कि निर्यात बढ़ाए बिना 12 से 14 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि दर संभव नहीं है। वस्तुओं के उत्पादन के मूल में ही वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा निहित है। जीडीपी को बढ़ाने के अलावा, कुल निर्यात में आयातित-इनपुट के हिस्से, व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे को कम करना भी जरूरी है। हमें नवाचार के लिए वैसे ही परिवेश की जरूरत है, जैसा सिलिकन वैली में मौजूद है। 'स्टेट ऑफ द यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रिपोर्ट, 2021' के मुताबिक, वैल्यू एडिशन का 71 फीसदी अंश अनुसंधान व विकास से जुड़ी गतिविधियां हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार, मूल्य श्रृंखला में अमेरिका की 38 फीसदी हिस्सेदारी की तुलना में चीन और ताइवान की हिस्सेदारी नौ-नौ प्रतिशत है, जबकि दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोप की क्रमशः 16 प्रतिशत, 14 प्रतिशत व 10 प्रतिशत है। जाहिर है, अनुसंधान और विकास बढ़ाकर हम अपने विनिर्माण क्षेत्र का स्तर ऊंचा कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण सोलर फोटोवोल्टिक मूल्य श्रृंखला है, इसमें 1980 से 2012 के बीच लागत 97 फीसदी घट गई, जिसकी एक बड़ी वजह विनिर्माण मूल्य श्रृंखला पर कब्जा करने की चीन सरकार की रणनीति थी। आज चीन इसके 80 फीसदी बाजार को नियंत्रित करता है। आने वाले दिनों में शायद ही उसे कोई पछाड़ सके। इसलिए विनिर्माण में मूल्य-वर्द्धन या आउटपुट रेशियो पर ध्यान देना जरूरी है। इस सुधार के लिए कुछ नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं। जैसे, प्रोत्साहन लायक उद्योगों की पहचान करना, मौद्रिक प्रोत्साहनों को तवज्जो देना, अकादमिक एवं उद्योग जगत की मदद से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना व उससे लाभ उठाना और मूल्य-वर्द्धन की सीमा को पूरा करने वाले उत्पादों की सरकारी खरीद आदि।

जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का अनुभव बताता है कि निर्यात बढ़ाए बिना 12-14 प्रतिशत की विनिर्माण वृद्धि दर संभव नहीं है।

साफ है, विनिर्माण को बेहतर बनाने से जुड़ी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मोर्चे पर बेहतर नतीजा मिल सकता है। यानी, रोजगार सृजन, उच्च विनिर्माण विकास दर, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनवरत प्रतिस्पर्द्धा और सेवा क्षेत्र में कौशल बढ़ाने जैसी चुनौतियों से हमें पार पाना ही होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)